Election Commission of India

NAME OF THE NEWS PAPER दैनिक जागरण DATE: 28 DEC 2012

वोट के लिए नोट योजना

केंद्र सरकार की ओर से क्रांतिकारी बताई जा रही नकद सब्सिडी योजना के उद्देश्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं हृदयनारायण दीक्षित

केंद्र का 'आधार' निराधार नहीं है। आधार कार्ड के जरिए गरीबों को सीधे नकदी देने की योजना नोट के बदले वोट का ही उपक्रम है। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्षों के सम्मेलन में 'नकदी आधार' को चुनावी जीत का आधार बताया है। योजना के अनुसार प्रत्येक गरीब के पास आधार नंबर होगा और इससे जुड़ा बैंक खाता होगा। योजना की शुरुआत जनवरी 2013 से 43 जिलों में होनी है। प्रथम चरण में पेंशन आदि कुछेक योजनाओं से जुड़ी नकदी गरीबों को सीधे दी जानी है। खाद्यान्न और खाद की सब्सिडी की नकदी बाद में दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने पहला आधार कार्ड महाराष्ट्र में जारी किया था, लेकिन महाराष्ट्र में भी आधार कार्ड धारकों की संख्या 50 प्रतिशत से कम है। 80 प्रतिशत आधार कार्ड इस योजना की प्राथमिक शर्त हैं। झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों के चयनित जिलों में भी आधार कार्ड का वितरण 40 प्रतिशत से भी नीचे है। देश की 70 प्रतिशत आबादी के पास बैंक खाते ही नहीं हैं। मनमोहन सरकार का लक्ष्य वोट के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार को भी खुश करना है। समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं, खाद्यान्न या खाद की सब्सिडी का धन निश्चित मद पर ही खर्च होता है। सीधे मिली नकदी का धन उसी मद पर खर्च होने की कोई गारंटी नहीं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों को सस्ते दर पर अन्न मिलता है। बेशक इस प्रणाली में तमाम भ्रष्टाचार है, लेकिन इसका संबंध किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्न खरीद से भी जुड़ा हुआ है। खाद्यान्न की जगह नकदी के चलन से भारतीय खाद्य निगम की खरीद सीमा घटेगी। गेहूं, चावल पैदा करने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित होंगे। नकदी पाए गरीब और सरकारी नीतियों से मजबूर किसान बाजार के भरोसे होंगे और महंगाई की मार झेलेंगे। बाजार लोककल्याण नहीं देखता। वह फसल के समय कम कीमत पर गेहूं चावल खरीदेगा और अभाव के समय महंगी दर पर बेचेगा। खाद्यान्न का मुक्त व्यापार विश्व व्यापार संगठन की पुरानी मांग है। मनमोहन सरकार बाजारवादी है। भारतीय खाद्य निगम

गरीबों की अनदेखी

- केंद्र गरीबों, किसानों की सब्सिडी काटकर राजकोषीय घाटा कम करना चाहता है, लेकिन पूंजीपतियों को पांच लाख करोड़ की छूट हर साल मिल रही है

को 'खाद्यान्न सुरक्षा' के मुख्य दायित्व से मुक्त करने की तैयारी है। 'सीधे नकदी पाओ' योजना का लक्ष्य गरीब कल्याण नहीं है। सरकार जनकल्याण की सारी योजनाएं बाजार को सौंप रही है। तर्क है कि ऐसी योजनाओं से राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है इसलिए गरीबों को सब्सिडी वाली योजनाओं में कटौती जरूरी है। सब्सिडी के खात्मे का अंतरराष्ट्रीय दबाव भी है।

केंद्र अमेरिकी अर्थशास्त्र का मनमोहन है, लेकिन अमेरिकी सब्सिडी पर ध्यान नहीं देता। अमेरिकी समाज में सब्सिडी की अपरिहार्यता है। केंद्र गरीबों, किसानों की सब्सिडी काटकर राजकोषीय घाटा कम करना चाहता है, लेकिन औद्योगिक घरानों को कोई पांच लाख करोड़ की छूट हर साल मिल रही है। असल में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित केलकर समिति ने राजकोषीय घाटा कम करने, खाद, अन्न और पेट्रोलियम आदि क्षेत्रों में सब्सिडी कटौती की सिफारिश की थी। समिति ने केरोसिन, रसोई गैस, डीजल, खाद और राशन के गेहूं चावल आदि की मूल्यवृद्धि की भी संस्तुति की थी। समिति ने ही इसके लिए खाद, अन्न और पेट्रोलियम सब्सिडी के नकद हस्तांतरण की सिफारिश की थी। केंद्र ने समिति के कहे अनुसार कीमतें बढ़ाई और 'नकदी पाओ' योजना शुरू की। गरीब को सस्ता अन्न देना सरकार का कर्तव्य है और देश के हर नागरिक को अन्न उपलब्ध कराना भी। ऐसे कार्यों में पूंजी लगाना श्रेष्ठतम निवेश क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री की सोच में राजकोषीय घाटे को कम करने का एकमात्र उपाय लोककल्याण से पल्ला झाड़ना है।

संप्रग सरकार गरीबी की परिभाषा भी नहीं कर पाई। 'गरीबी की रेखा' मजाकिया मुहावरा है। विकास दर के आंकड़े झूठे हैं। लाखों किसान आत्महत्या को विवश हैं। अभावग्रस्त लाखों लोगों के पास गरीबी की रेखा के नीचे वाले-बीपीएल कार्ड नहीं हैं। यह हालत तब है जब अर्जुन सेनगुप्ता से लेकर तेंदुलकर समिति तक ने 80 फीसद लोगों के भयावह अभावों की चर्चा की है। केंद्र गरीबी की वास्तविकता पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, लेकिन केलकर समिति के गरीब विरोधी सुझावों को जस का तस मान रहा है। चंद नकद नोट समस्या का समाधान नहीं हैं। गरीबों को हरेक स्तर पर प्रत्यक्ष सहायता चाहिए। अब बाजार ही सरकार और देश का नियंता है। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा बाजार के पास है। अन्न सुरक्षा भी बाजार तय करेगा। केरोसिन तेल भी बाजार मूल्य पर। खाद भी बाजार मूल्य पर। संप्रग नकदी की ताकत जानता है। यहां हर चीज बिकाऊ है। संप्रग की सोच में मतदाता भी है। पीछे आम चुनाव में किसानों की कर्ज माफी की गई थी। अनेक अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले की आलोचना की थी, लेकिन संप्रग ने उसे चुनावी मुद्दा बनाया था। कांग्रेस नकद नोट से नकद वोट पाना चाहती है। 2014 का चुनाव संप्रग के लिए खतरा है। सो लोककल्याणकारी राज्य की सारी मान्यताएं ताक पर रखकर 'सीधे नकदी लो' की योजना है, लेकिन आमजन सतर्क हैं। सरकार जिम्मेदारी नहीं निभाती तो मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं।

(लेखक उप्र विधानपरिषद के सदस्य हैं)

response@jagran.com